(ग) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार "बाल्को" को बाक्साइट की सप्लाई नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन अन्य स्रोतों से "बाल्को" को बाक्साइट सप्लाई किए जाने को संभावना है ताकि कारखाने के उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) इस समय गंधमर्दन में अपनी निजी बाक्साइट खान का विकास कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में फुटकापहाड़ तथा अमरकंटक स्थित दोनों बाक्साइट खानों का प्रतिस्थापन किया जा सके, जिनके भंडार तेजी से घटते जा रहे हैं। अमरकंटक तथा फुटकापहाड़ में खनन के अलावा, बाल्को इस समय उत्तर प्रदेश राज्य खनन विकास निगम तथा मध्य प्रदेश राज्य खान विकास निगम से भी कुछ मात्रा में बाक्साइट की खरीद करके अपनी जरूरत पूरी कर रही है। उड़ीसा राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से बाक्साइट पूर्ति के बारे में बाल्को को अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

नावथा में ताप्ती नदी पर बांध बनाने की संयुक्त योजना

544. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने नावथा में ताप्ती नदी पर बांध बनाने की कोई संयुक्त योजना तैयार की थी और क्या इस प्रयोजन हेतु कोई शिलान्यास किया गया था;

(ख) उक्त बांध को बनाने हेतु दोनों राज्यों में हुए करार का ब्यौरा क्या है तथा इसके निर्माण में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है; और

(ग) इस परियोजना में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने नावथा में ताप्ती नदी पर एक संयुक्त परियोजना का निर्माण करने और जल तथा लागत में सहभागिता की सहमति दी है। केन्द्र सरकार द्वारा लागत में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। नावथा बांध की आधार-शिला रखे जाने के बारे में केन्द्र को कोई जानकारी नही है।

(ग) परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, यह पता चला है कि यह निर्माण के प्रारम्भिक चरण में है।

मध्य प्रदेश में सुलभ शौचालयों का निर्माण

545. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कितने गांवों में सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया हैं तथा उनकी निर्माण लागत कितनी आई है;

(ख) इन शौचालयों में से कितने शौचालय संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि शौचालयों के निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गई हैं तथा इनके निर्माण का स्तर घटिया है;

(घ) क्या इसकी जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग